

भारत में मानहानिकानून में सुधार का समय

“ [Penalty in proportion: On growing use of criminal defamation proceedings](#) ” 24/09/2025

प्रलिसि के लिये: [मानहाना, भारतीय न्याय संहिता](#) की धारा 356, [अनुच्छेद 21](#), [सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ \(2016\)](#), “[बॉर्नार्ड स्टैंडर्ड](#)”, [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A](#)

मेन्स के लिये: भारत में मानहानिसे संबंधित हाल के मामले, भारत में मानहानिको अपराध से मुक्त करने के पक्ष और वपिक्ष के मुख्य तर्क

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आपराधिक मानहानिके मामले में अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दिया है, एक सुनवाई के दौरान कहा कि ‘इस सब को अपराध से मुक्त करने का समय आ गया है।’ यह टिप्पणी तब की गई जब [फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म](#) की एक याचिका पर विचार किया जा रहा था, जिसमें आपराधिक मानहानिके मामले में जारी [समन को रद्द](#) करने की मांग की गई थी। यह टिप्पणी इस बात की चिंता को दर्शाती है कि मानहानिकानून का दुरुपयोग आलोचकों और पत्रकारों को डराने के लिये किया जा रहा है। यह भारत जैसे लोकतंत्र में प्रतष्ठा की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने पर महत्वपूर्ण बहस उठती है।

कानून में मानहानिकी अवधारणा क्या है?

- परचिय: मानहानि का तात्पर्य किसी भी मौखिक या लिखित कथन से है, जो शब्दों या अभिव्यक्तियों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की प्रतष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।
 - मानहानिके प्रकार:
 - लाइबेल (Libel): ऐसा मानहानिकारक कथन जो लिखित, प्रकाशित या दृश्य रूप में होता है।
 - सलैंडर (Slander): ऐसा मानहानिकारक कथन जो मौखिक रूप में कहा जाता है और प्रतष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।
- भारत में कानूनी आधार: भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानिको किसी व्यक्ति की प्रतष्ठा को हानि पहुंचाने के आशय से या यह जानते हुए कि इससे हानि होगी, किसी आरोप को बनाना या प्रकाशित करना पराभिषिक्त किया गया है।
- संवैधानिक औचित्य: न्यायालय प्रतष्ठा को अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत मानती है और प्रतष्ठा को होने वाले नुकसान को सामाजिक सद्भाव पर प्रभाव डालने वाला मानती है।
- अपराध का दायरा: यह जीवित व्यक्तियों, मृत व्यक्तियों, कंपनियों, संगठनों पर लागू होता है और इसमें व्यक्तिगत या वैकल्पिक रूप से किये गए कथन भी शामिल हैं।
 - क्षति में शामिल है किसी व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम आंकना, जातियां पेशे की प्रतष्ठा को नुकसान पहुंचाना, आर्थिक विश्वसनीयता (creditworthiness) को प्रभावित करना या किसी व्यक्ति के शरीर के संबंध में अपमानजनक धारणा उत्पन्न करना।
- नागरिक बनाम आपराधिक मानहानि:
 - सिविल (Civil): नज्जी अपराध; इसके उपायों में प्रतष्ठा को हुए नुकसान के लिये मुआवज़ा शामिल है।
 - क्रिमिनल (Criminal): सार्वजनिक अपराध; दंड के रूप में जुरमाना या कारावास का प्राधान, ताकि दुर्भावनापूर्ण हमलों को रोका जा सके।

- आपराधिक दायित्व के तत्त्व: आपराधिक दायित्व उत्पन्न होने के लिये तीन तत्त्व वदियमान होना आवश्यक हैं: कथन मानहानिकारक होना चाहिये, यह किसी वशिष्ट व्यक्ति या स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य समूह की ओर नरिदेशति होना चाहिये और इसे कम से कम एक ऐसे व्यक्ति तक प्रकाशति या संप्रेषति कयिा जाना चाहिये जो याचकिाकरत्ता नही है।
 - नागरकि दायित्व (Civil Liability) से भन्ति, आपराधिक कानून में यह सदिध करना आवश्यक है कहिानपिहुँचाने का आशय था या यह ज्ञान था कहिानाहोने की संभावना है।

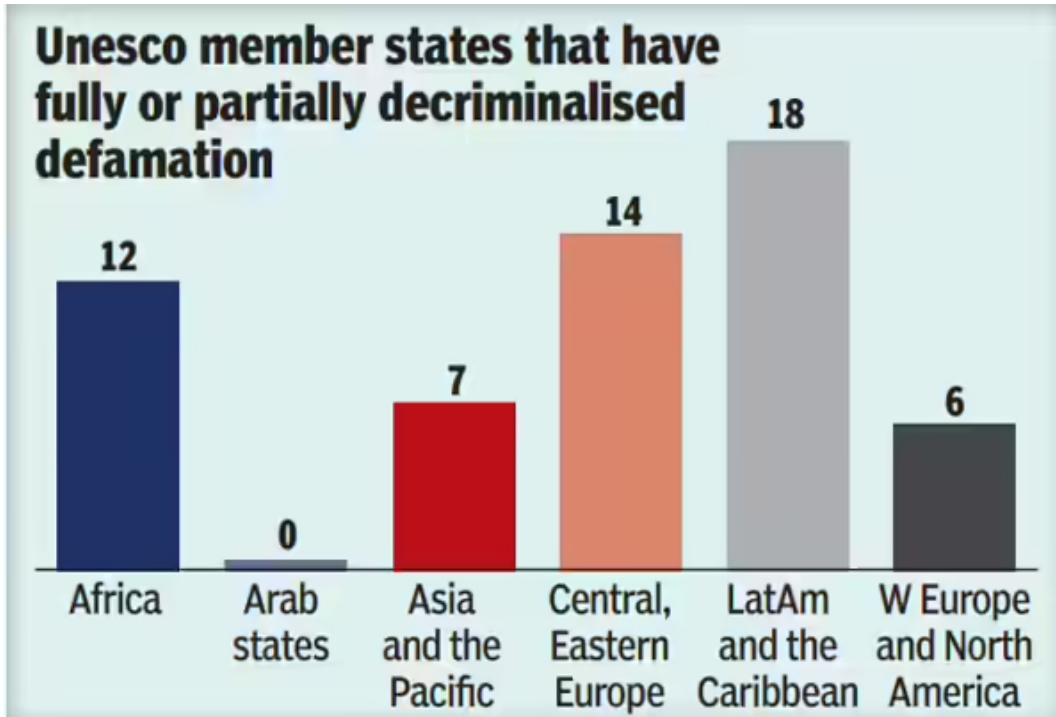
भारत में मानहानिसे संबंधति हाल के न्यायकि मामले क्या हैं?

- सुव्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016): सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धाराओं 499 एवं 500 (अब BNS 2023 की धारा 356) के तहत आपराधिक मानहानि की संवैधानकिता को बरकरार रखा, यह नरिणय देते हुए कहिआपराधिक मानहानिअनुच्छेद 19(2) के तहत अभवियक्ती की स्वतंत्रता पर एक उचति प्रतबिंध है तथा प्रतषिठा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हसिसा है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वाक् और अभवियक्ती की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतषिठा की रक्षा के बीच संतुलन बनाने पर ज़ोर दिया, यह कहते हुए कि, "Reputation of one cannot be allowed to be crucified at the altar of the other's right of free speech अर्थात् किसी एक की प्रतषिठा को दूसरे के अभवियक्ती के अधिकार के लिये नष्ट नहीं की जा सकती।"
- एम.जे. अकबर बनाम प्रयिा रमानी (2021): एक प्रमुख #MeToo मामले में, दलिली न्यायालय ने प्रयिा रमानी को एम.जे. अकबर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि आरोपों से बरी कर दिया, यह कहते हुए कगिरमिा का अधिकार और यौन उत्पीडन से सुरक्षा, अकबर के प्रतषिठा के दावे से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
 - मानहानि के मामलों में सत्य और सार्वजनकि हति को वैध बचाव के रूप में मान्यता दी गई।
- इसी प्रकार, हाल ही में समीर वानखेडे बनाम नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट मामले (दलिली उच्च न्यायालय, सतिंबर 2025) में, मानहानि का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है, जो अभवियक्ती की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतषिठा की सुरक्षा के बीच तनाव को रेखांकति करता है।
- राहुल गांधी 'मोदी' मामला (2019-वर्तमान): राहुल गांधी को सूरत मजसिद्रेट कोर्ट ने "मोदी" उपनाम के बारे में की गई टपिपणी के लयिदोषी ठहराया था, जसिमें कथति तौर पर मोदी समुदाय का जकिर था।
 - उनकी दोषसदिधि के कारण उन्हें संसद से अस्थायी रूप से अयोग्य घोषति कर दिया गया और उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। इस मामले ने समूह मानहानि और राजनीतिक भाषण पर सवाल खड़े कर दयि हैं।
- अडानी गैंग ऑर्डर और मीडिया नषिधाज्जा (2025): दलिली की एक अदालत ने हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ कथति रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशति करने से पत्रकारों को प्रतबिंधति करने वाले गैंग ऑर्डर को रद्द कर दिया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने "बोनार्ड मानक" को दोहराते हुए कहा कि पूर्व-परीक्षण नषिधाज्जा दुरलभ होनी चाहिये और केवल तभी उचति होनी चाहिये जब प्रतविादी कथति मानहानि का बचाव नहीं कर सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का अवलोकन: सतिंबर 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने मानहानि को अपराधमुक्त करने की संभावना का संकेत दया था तथा सुझाव दया था कि औपनविशकि युग का यह अपराध आधुनकि लोकतंत्र के लयि उपयुक्त नहीं हो सकता है।
 - चल रहे मामले में जेएनयू के एक प्रोफेसर और 'द वायर' शामिल हैं, जसिमें पीठ ने BNS की धारा 356, जो पहले IPC की धारा 499 थी, की प्रासंगकिता और आवश्यकता पर खुले तौर पर बहस की।

भारत में मानहानि को अपराधमुक्त करने के पक्ष में प्रमुख तर्क क्या हैं?

- अभवियक्ती की स्वतंत्रता की रक्षा: आपराधिक मानहानि कानूनों का अभवियक्ती की स्वतंत्रता पर "चीलिंग इफेक्ट" पड़ता है, यह पत्रकारों, वृहसिल-ब्लोअर्स और नागरिकों को वैध आलोचना या असहमतवियक्त करने से रोकता है, जसिके परिणामस्वरूप वे स्वयं ही सेंसरशपि (self-censorship) करने लगते हैं।
 - सतिंबर 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं नोट कयिा कि आपराधिक अभयिोजन का डर अनुच्छेद 19(1)(ए) अधिकारों के प्रयोग को प्रतबिंधति करता है और नागरकि उपचार प्रतषिठा को होने वाले नुकसान को पर्याप्त रूप से संबोधति करते हैं।
 - श्रेया सधिल बनाम भारत संघ (2015) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन मानहानि पर आपराधिक धारा (आईटी अधनियम की धारा 66 A) को रद्द कर दिया, क्योकि यह अस्पष्ट थी और मुक्त भाषण पर नकारात्मक प्रभाव डालती थी।
- दुरव्यवहार और उत्पीडन को रोकना: आपराधिक मानहानि राजनेताओं, अभनिताओं और उद्योगपतयिों जैसे शक्तिशाली व्यक्तयिों के लयि सार्वजनकि भागीदारी के खिलाफ रणनीतिक मुकदमे (SLAPP) दायर करने का एक हथयिर बन गया है।
 - हाल के उदाहरणों में सरकारी और कॉर्पोरेट आचरण पर रपिर्गति करने के लयि पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई कई FIR शामिल हैं, एडटिर्स गलिड ने कहा कि आपराधिक सम्मन का जवाब देने की प्रक्रयिा भी "प्रक्रयिा द्वारा दंड" के रूप में कार्य करती है तथा स्वतंत्र पत्रकारता को दबाती है।
- न्यायकि लंबति मामलों और वलिंब को कम करना: मानहानि के मुकदमों के कारण नचिली अदालतें अवरुद्ध हो जाती हैं और नजिी वविादों के लयि वशिाल न्यायकि संसाधनों का उपभोग होता है।
 - सतिंबर 2025 में वायर-जेएनयू मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हज़ारों आपराधिक मानहानि मामलों में लंबी मुकदमेबाजी और देरी पर गौर कयिा, जो अक्सर वर्षों तक चलती है, जसिसे बहुमूल्य न्यायकि समय बर्बाद होता है, जो गंभीर अपराधों के लयि आरक्षति कयिा जा सकता है।
- प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा: कानूनी वशिषज्जों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आपराधिक मानहानि से मीडिया पर अंकुश लगने और लोकतांत्रकि बहस को दबाने का खतरा है।
 - अप्रैल 2025 में पंजाबी ट्रबियून और ट्रबियून संपादकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को खारजि करना यह दर्शाता है कि ज़मिमेदार रपिर्गति को आपराधिक नहीं माना जाना चाहिये, खासकर तब जब पत्रकारों को चुप कराने के लयिरणनीतिक मुकदमों का सामना करना पड़ता है।

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (2025) में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर है, जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता के लिये महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करता है।
- लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखना: सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी हालिया टिप्पणी में इस बात पर जोर दिया कि प्रतियोगिता की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिये, लेकिन लोकतांत्रिक बहुलवाद और आलोचनात्मक संवाद की कीमत पर नहीं।
 - अपराधमुक्त कानून को गरिमा, बंधुत्व और पारस्परिक सम्मान जैसे संवैधानिक मूल्यों के साथ पुनः संरेखित करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अधिकार दूसरे के “वेदी पर बलदान” न हो।
- वैश्विक मानकों के अनुरूप: पत्रकारों की सुरक्षा समिति और UNHRC सहित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, भारत से आपराधिक मानहानि कानूनों को नरिसत करने का आग्रह करते हैं।
 - प्रतियोगिता को हुआ आघात मुख्यतः एक नागरिक अपराध है, जिसका पर्याप्त उपचार आर्थिक क्षतिपूर्ति, नषिधाज्जा, सार्वजनिक क्षमा-याचना या बयान वापसी के माध्यम से किया जा सकता है।
 - कई देशों ने ऐसे आपराधिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया है, यह मानते हुए कि इनका प्रभाव स्वतंत्र मीडिया और नागरिक सक्रियता पर असंगत रूप से अधिक पड़ता है।



भारत में मानहानि को अपराधमुक्त करने के विरुद्ध प्रमुख तर्क क्या हैं?

- मौलिक अधिकार के रूप में प्रतियोगिता की सुरक्षा: सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि प्रतियोगिता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है तथा आपराधिक मानहानि अनुच्छेद 19(2) के तहत एक उचित प्रतिबंध है।
 - आपराधिक दंड को बनाए रखने से प्रतियोगिता पर अन्यायपूर्ण हमलों के लिये त्वरित नविवरण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
- दुर्भावनापूर्ण और गैर-जम्मेदाराना भाषण के खिलाफ रोकथाम: डिजिटल युग में, झूठी जानकारी तुरंत और अपूरणीय रूप से फैल सकती है।
 - कानूनी विशेषज्ञों और वधि आयोग (2023) ने तर्क दिया कि आपराधिक कानून जानबूझकर और लापरवाही से मानहानिकारक सामग्री के प्रसार के खिलाफ एक शक्तिशाली नविवारक के रूप में कार्य करता है, जिससे फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने और व्यक्तियों को अपूरणीय क्षति से बचाने में मदद मिलती है।
 - भारतीय वधिआयोग की 285वीं रिपोर्ट में आपराधिक मानहानि को नये आपराधिक कानूनों के एक भाग के रूप में बनाये रखने की सफारिश की गयी है।
 - SMC न्यूमेटिक्स बनाम जोगेश कवात्रा (2004) मामले में, दलिली उच्च न्यायालय ने पहला भारतीय साइबर मानहानि नषिधाज्जा जारी की, जिसमें मानहानिकारक ईमेल और इंटरनेट पोस्ट को मानहानि कानून के तहत कार्रवाई योग्य माना गया।
- सामाजिक बहिष्कार से सुरक्षा: सविलि मानहानि के मामले लंबे और महंगे होते हैं इसके विपरीत, आपराधिक अभियोजन एक लागत प्रभावी और सुलभ उपाय प्रदान करता है, जो उन लोगों को सशक्त बनाता है, जिनमें अन्यथा हानिकारक अफवाहों के कारण सामाजिक बहिष्कार या आजीविका के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
- कमजोर समूहों की सुरक्षा: आपराधिक मानहानि हिंसा पर पड़े या कमजोर समुदायों के लिये सुरक्षा कवच का कार्य कर सकती है, जिनकी प्रतियोगिता को वशिष रूप से नुकसान पहुँचाने की आशंका होती है।
 - उदाहरण के लिये, महिलाओं, दलितों या अल्पसंख्यक समूहों को नशाना बनाकर दिये गए अपमानजनक बयान सामाजिक भेदभाव या उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं।
 - आपराधिक प्रावधान त्वरित जवाबदेही और नविवरण सुनिश्चित करते हैं, जो सविलि मुकदमेबाजी के कारण वलिंबति या दुर्गम हो सकता है।

- **लोक व्यवस्था बनाए रखना:** लापरवाह या दुर्भावनापूर्ण बयान समुदाय में अशांति भड़का सकते हैं और टकराव को बढ़ा (वशिषकर भारत के सामाजिक रूप से संवेदनशील वातावरण में) सकते हैं।
 - **आपराधिक मानहानि प्रवाधान** ऐसे व्यवहार पर अंकुश लगाने, **व्यापक मतभेद के जोखिम को कम करने** तथा **सार्वजनिक व्यवस्था** की रक्षा करने का कार्य करते हैं।

भारत में मानहानि कानून के लिये कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

- **नज़्ज़ी मानहानि को अपराधमुक्त करना, जनहति के लिये आपराधिक मानहानि को बरकरार रखना :** कानूनी वशिषज्ज़ों द्वारा सुझाया गया एक संतुलित दृष्टिकोण यह है कि आपराधिक मानहानि को केवल जनहति, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े मामलों तक ही सीमिति रखा जाए, जबकि नज़्ज़ी प्रतषिठा संबंधी वविादों को पूरी तरह से सविलि अदालतों में स्थानांतरित करना।
 - इससे आम नागरिकों की अभवियक्ता की स्वतंत्रता की रक्छा होगी और साथ ही समाज को प्रभावति करने वाले बेवजह झूठ के लिये मज़बूत नविरक सुनश्चिति होंगे।
 - वैश्वकि स्तर पर, अधकिांश लोकतंत्र मानहानि को एक नागरकि अपराध मानते हैं, जहाँ पीड़ति आर्थकि मुआवज़ा और सुधारात्मक आदेश की माँग करते हैं।
- **सविलि मानहानि की कार्यवाही को मज़बूत और तीव्र करना:** मानहानि में ज़्यादातर नुकसान न्याय में वलिंब से होता है।
 - भारत को सविलि मानहानि के मामलों को स्पष्ट समय-सीमा और उचित मुआवज़े की सीमा के साथ नपिटाने के लिये त्वरति अदालतें या समरपति पीठें स्थापति करनी चाहिये, ताकि भाषण को आपराधिक बनाए बनिा प्रभावी और समय पर समाधान मलि सके।
 - ब्रिटिन जैसे देशों ने मानहानि सुधार अधनियमों के साथ-साथ आधुनकि सविलि कानूनों पर भरोसा कयिा है, जसिसे कारावास के भय के बगैर संतुलति सुरक्छा सुनश्चिति होती है।
- **एंटी-SLAPP (जनभागीदारी के वरिद्ध रणनीतिक मुकदमा) कानून लागू करना:** शक्त्तशाली वयक्ता और नगिम आलोचकों को महंगे मुकदमेबाजी से डराने के लिये SLAPP मुकदमों का इस्तेमाल करते हैं।
 - अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह एंटी-SLAPP कानून लागू करने से पत्रकारों, कार्यकरत्ताओं और नागरिकों को मुकदमेबाजी के दुरुपयोग से बचाया जा सकेगा, साथ ही वास्तवकि मानहानि के दावों को आगे बढ़ने की अनुमति मलिगी।
- **नषिपक्छ आलोचना और जनहति पर वशिषिट न्यायकि दशानरिदेश प्रदान करना:** सर्वोच्च न्यायालय की टपिपणयिों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए, नषिपक्छ आलोचना, वयंग्य और राय को दुर्भावनापूर्ण मानहानि से अलग करने के लिये स्पष्ट न्यायकि सिद्धांतों को संहतिबद्ध कयिा जाना।
 - इससे न्यायालयों को मानहानि के मामलों में नषिपक्छ नरिणय लेने में सहायता मलिगी और साथ ही अभवियक्ता पर मनमाने प्रतर्बिधों से भी बचा जा सकेगा।
- **मीडिया साक्छरता और ज़मिमेदार भाषण के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना:** ज़मिमेदार भाषण को प्रोत्साहति करने और नागरिकों को आलोचना एवं मानहानि के बीच अंतर के बारे में शक्त्ति करने से उक्त्त मामलों में कमी आ सकती है।
 - **सरकार, नागरकि समाज और मीडिया जागरूकता** अभयानों में सहयोग कर सकते हैं, जैसा कि सक्रयि नागरकि शक्त्ति वाले देशों में देखा गया है, जसिसे सामाजकि तनाव और कानूनी वविाद कम होते हैं।

नषिक्छ:

भारत में मानहानि कानूनों में सुधार हेतु **अभवियक्ता की स्वतंत्रता** और **प्रतषिठा की सुरक्छा** के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है। जैसा कि **जॉन सटुअरट मलि** ने (ऑन लबिर्टी में) तर्क दयिा था, "किसी राय को दबाना मानवता की गलती को सक्छाई से बदलने के अवसर से वंचति करना है, जसिसे आलोचनात्मक वचिर और लोकतांत्रकि जवाबदेही का गला घोट दयिा जाता है।" इस प्रकार, वयक्त्तगित मानहानि को अपराधमुक्त करना, नागरकि उपचारों को सुदृढ़ करना और SLAPP वरिधी उपाय लागू करना पत्रकारों और नागरिकों की रक्छा कर सकता है, ज़मिमेदार संवाद को बढ़ावा दे सकता है और संवैधानकि स्वतंत्रता एवं सामाजकि न्याय, दोनों को बनाए रख सकता है।

QUESTION QUESTION QUESTION:

भारत में आपराधिक मानहानि कानूनों की प्रायः आलोचना की जाती है क्योंकि ये स्वतंत्र अभवियक्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मानहानि वधिकि सुधारों के माध्यम से भारत संवैधानकि रूप से प्रदत्त स्वतंत्र अभवियक्ता के अधिकार और प्रतषिठा की सुरक्छा के बीच कैसे संतुलन बना सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्छा, वगित वर्ष के प्रश्न

QUESTION QUESTION QUESTION

प्रश्न. नज़्ज़िता के अधिकार को जीवन एवं वयक्त्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के अंतरभूत भाग के रूप में संरक्छति कयिा जाता है। भारत के संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपर्युक्त्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है? (2018)

(a) अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।

(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दएि गए राज्य की नीतिके नदिशक तत्त्व।

(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।

(d) अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

उत्तर: C

?????

प्रश्न. आप "वाक् और अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य" संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फलिमें अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनकि भन्नि स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिए। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/time-to-reform-defamation-laws-in-india>

